International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 2, Issue 5, pp: 913-917 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

भारत-नेपाल भू राजनीतिक सम्बन्ध

डॉ0 पुष्पा कुमारी

इतिहास विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा-846008 (बिहार)

Date of Submission: 30-08-2020 Date of Acceptance: 15-09-2020

भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके सदियों से घनिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। वस्तुतः अपने देश जैसा लगता है विदेश नेपाल, जिसकी यात्रा के लिए भारतीयों को आज भी न किसी पासपोर्ट की जरूरत है न वीजा की और ना ही ढ़ेर सारे पैसों की। दोनों की धार्मिक मान्यताएँ भी लगभग एक जैसी हैं। भारत में लाखों नेपाली काम करते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिशकाल से नेपाल के गुरखा सिपाही भारतीय सेना में अपनी वीरता का परिचय देते आ रहे हैं। इतने गहरे संबंध शायद ही किन्हीं अन्य दो देशों में हों। लेकिन खेद की बात है कि हाल के वर्षो में दोनों के रिश्तों में काफी दूरियाँ आयी हैं। इसके कई कारण हैं। नेपाल के कट्टरपंथी तत्व, चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत की उदासनीता। यह इसी से स्पष्ट है कि भारत के लिए भू-राजनीतिक स्थिति और अन्य कारणों से इतने महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में पिछले 47 वर्ष से भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, जबकि इस बीच चीनी प्रधानमंत्री समेत तीन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने नेपाल की यात्रा की और नेपाली प्रधानमंत्री समेत सात उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चीन गये। नरेन्द्र मोदी ने सार्क संगठन के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पद के अपने शपथग्रहण समारोह में जिन देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया उनमें नेपाल भी था जिसके प्रधानमंत्री सुशील कोइराला अप्ल सूचना पर दिल्ली पहुँच गये। 47 वर्ष की इस अवधि में नेपाल में माओवादियों ने भारी उत्पात मचाया, वहाँ राजशाही का अंत हो गया और अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गयी। हालांकि वर्षों से संविधान निर्माण की प्रक्रिया लटकते रहने से वहाँ राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। हालात धीरे-धीरे बदलने लगे हैं। चीनी प्रभाव के कारण नेपाल की भारत पर निर्भरता घटती जा रही है। नेपाल अब वह नेपाल नहीं रहा जो 4950 में भारत-नेपाल मैत्री संधि के समय था और भारत के साथ मधुर संबंधों का पक्षधर था। वर्तमान सरकार ने नेपाल के साथ संबंध सुधारने की जो पहल की है वह उनकी पुरजोर राजनीतिक व कूटनीतिक सूझबूझ की परिचायक है।

इतिहास के इस क्रम में दोनों देशों ने अपने सम्बन्धों में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। 24वीं सदी आरम्भ से ही नेपाल की राजनीति एवं समाज बदलाव का साक्षी रहा है। अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों ने जिसमें माओवादी, लोकतांत्रिक, मघधेसी एवं जनजातीय आंदोलन प्रमुख हैं, जिसने नेपाल की समाज और राजनीति में प्रगतिशील मूल्यों के समावेश करने के साथ-साथ पुराने शोषणकारी, विषमकारी तत्वों को खारिज कर दिया।

आज नेपाल राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, राजतन्त्र से गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। यह परिवर्तन इतना आसान नहीं रहे हैं। नेपाल की घरेलू राजनीति एवं समाज में घटित हुए घटनाक्रम ने दोनों देशों के सम्बन्धों को प्रभावित किया है। इस परिपेक्ष्य में, भारत-नेपाल सम्बन्ध की महत्ता को समझना अनिवार्य है।

भारत की सामरिक हितों के साथ-साथ ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषीय समानता के कारण 4950 में दोनों देशों ने 'शांति और मित्रता की संधि' के द्वारा इस सम्बन्धों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया।

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 2, Issue 5, pp: 913-917 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

वर्तमान में नेपाल को इस संधि पर आपत्ति है। इसके अनुसार यह संधि नेपाल की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता के विपरीत है। लेकिन 4950 यह कि संधि नेपाल के लिए एक 'सेफ्टी वाल्व" की भांति काम करता है, क्योंकि इस संधि के तहत दोनों देश के बीच खुली सीमा का प्रावधान है, जिसके तहत दोनों देश की जनता निर्बाध रूप से आवागमन कर सकती है। इस संधि के प्रावधानों के तहत ही नेपाल की 2.8 मीलियन लोग भारत में काम और निवास करते हैं।

भारत में नेपाल मामलों के जानकार प्रो. डी. मुनी के अनुसार संधि में 'सकारात्मक विभेद' की गयी है, जो नेपाल की पक्ष में है। भारत का मानना है कि यह संधि भारत नेपाल के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का बड़ा प्रमाण है तथा निवर्तमान भारतीय सरकार इस संधि के पुनर्विलोकन हेतु तैयार है।

भारत एंव नेपाल की भौगोलिक समीपता, एकरूपता तथा दोनों देशों के बीच लंबी खुली सीमा एवं चीन का नेपाल के साथ साझी सीमा होने के कारण, नेपाल भारत की उत्तरी सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

वर्तमान सरकार की पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में जान फूंकी दी है। हजारों साल पुराने दरकते रिश्ते को नयी ऊँचाई देते हुए 17 साल के खालीपन को मिठास से भर दिया हैं नेपाल की संसद में मोदी के भाषण की सराहना न केवल भारत-नेपाल में हो रही है बल्कि विश्व समुदाय भी स्वागत कर रहा है। मोदी ने अपने दिए भाषण में नेपाल को विश्वास दिलाया कि वह भारत के सवा करोड़ लोगों की ओर से दोस्ती और सद्भावना का संदेश लेकर आए हैं और उनकी इच्छा है कि भारत और नेपाल विकास की डगर पर कंधा से कंधा मिलाकर चलें। यह कितना सुखद है कि कल तक जो माओवादी नेता भारत को अपना विरोधी मानते थे वह भी संसद में मोदी के नेपाल प्रेम से अभिभूत दिखे। मोदी ने अत्यंत सहज भाव से नेपाल की संसद में भारत के विचारों को रखा और दोनों देशों के रिश्ते को गंगा और हिमालय की तरह अटूट और पवित्र बताया। पहाड़ की पानी और जवानी का उल्लेख कर संदेश दिया कि दोनों देशों का विकास परस्पर निर्भरता से ही संभव है। गौर करें तो मोदी ने अक्टूबर 1956 में नेपाल की यात्रा पर गए भारतीय राष्ट्रपति डा0 राजेंद्र प्रसाद के उस वक्तव्य को ही आगे बढ़ाया है जब उन्होंने कहा था कि नेपाल की शांति व सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा नहीं है। नेपाल के मित्र हमारे मित्र हैं और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु हैं। यह सच्चाई भी हैं कि हिमालय की उपत्य में बसे नेपाल का भारत से ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध रहा है। भारत ने सदैव बड़े भाई की तरह नेपाल से व्यवहार किया है और नेपाल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत कर लेने के बाद भारत-चीन संबंधों में नेपाल की सामरिक स्थिति का महत्व बढ़ गया है। यह उचित है कि मोदी ने नेपाल की मदद के लिए कुछ अहम घोषणाएँ की है जिनमें नेपाल के विकास के लिए दस हजार करोड़ नेपाली रूपए की सहायता देने के अलावा नेपाली छात्रों के लिए भारतीय संस्थानों में छात्रवृत्ति दिया जाना शामिल है। मोदी ने नेपाल की संसद को यह भी अहसास कराया कि उनके पास भारत को रोशन करने की असीम शक्ति है और वह पन बिजली के रूप में अपनी जलशक्ति का उपयोग करके नेपाल को खुशहाल बना सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत की इच्छा नेपाल को हिट करने यानी हाइवे, आइवे और ट्रांसवे के क्षेत्र में सहायोग देने की है। गौर करें तो नेपाल के विकास कार्यों में अधिक धन भारत का ही लगा हुआ है। कोलंबों योजना के तहत भारत अनेक नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण दिया है। आजादी के बाद से ही भारत नेपाल को हर तरह का प्रशिक्षण, तकनीकी और गैर तकनीकी सहयोग देता रहा है। भारत ने नेपाल की कई परियोजनाओं में बढ़-चढ़कर सहयोग दिया है। इनमें देवी घाट, त्रिशुल करनाली और पंचेश्वर जल विद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत त्रिभुवन गणपथ, काठमांडु त्रिशुली मार्ग तथा त्रिभुवन हवाई अड्डा के निर्माण में भी भरपूर सहयोग किया है। इसके अलावा भारत नेपाल के भू-वैज्ञानिक अनुसंधान तथा खनिज खोजबीन के काम में भी मदद करता है। भारत के काठमांडु घाटी के एक उप नगर पाटन में एक औद्योगिक बस्ती की भी स्थापना की है। विडंबना यह है कि भारत के भरपूर सहयोग एवं ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद भी नेपाल के मन में कुछ

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 2, Issue 5, pp: 913-917 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

आशंकाएं हैं। मसलन वह अब भी भारत के संदर्भ में जुनियर भागीदार के मनोविज्ञान से ग्रसित है तथा दक्षिण के पड़ोसी के आधिपत्य की आशंका का भूत उसे सताता रहता है। नेपाल भारत और चीन के साथ समदूरी सिद्धांत के आधार पर संबंधों का निर्वहन चाहता है। गौर करें तो यह उसकी परंपरागत नीति है। 1769 में आधुनिक नेपाल की स्थापना के साथ ही उसके निर्माता पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की विदेश नीति निर्धारित कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नेपाल देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान हैं। हमें चीनी सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए तथा हमारे संबंध दक्षिणी सागरों के सम्राट से भी संबंध मधुर होना चाहिए। नेपाल उसी नीति पर कायम है। हालांकि मोदी ने दोनों के रिश्तों पर जीम बर्फ को पिघलाकर दोनों बीच सहयोग और भरोसे का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अच्छी बात यह है कि नेपाल ने भी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत से समझौता करने को हामी भरी है। एक समझौते के तहत दोनों ने महाकाली नदी पर सहमति की मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि यह परियोजना महाकाली नदी पर 5600 मेगावाट की पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के काम शुरू करने पर सहमति की मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि यह परियोजना महाकाली नदी पर समन्वित संधि के तहत आती है और इस पर 1996 में हस्ताक्षर हुआ था। नेपाल के लोगों का दिल जीतने और उनके मन में भारत को लेकर ढेरों आशंकाओं को मोदी ने दूर करने के लिए एक तरह से अफसोस जताया कि दोनों देशों के बीच दूरी अत्यंत कम होने के बावजूद भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचने में 17 साल लग गए। उनके इस भावुक बयान से नेपाल की संसद भावुक दिखी। गौरतलब है कि इंद्र कुमार गुजराल के बाद द्विपक्षीय यात्रा पर नेपाल जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 17 साल के इस कालखंड में दोनों देशों में किसी ने भी आगे बढ़कर संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश नहीं की और उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हुई और आर्थिक प्रगति का मार्ग भी अवरूद्ध हुआ। हालात तब ज्यादा बिगड़ा जब 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने नेपाल को अनाज, तेजल और गैस की आपूर्ति बंद कर दी। सिर्फ इसलिए कि काठमांडों स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी को प्रवेश और पूजा-अर्चना की अनुमति नहीं मिली। भारत के प्रतिबंध के बाद नेपाल की जनता सड़क पर उतरी और भगत विरोधी नारे लगाए और इसका फायदा चीन उठाने में सफल रहा। नेपाल के राजनीतिक जीवन में चीन अपनी आर्थिक ताकत के बूते एक तरह से निर्णायक भूमिका में आ गया है। नेपाली शासक और चीन के प्रबल पक्षधर राजा ज्ञानेंद्र को नेपाली जनता द्वारा खारिज किए जाने के बाद भी आज वहाँ चीन की पक्षधरता करने वालो की कमी नहीं है। नेपाल में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो अपने यहाँ चीन की दखलादाली को अनुचित नहीं मानता। यह सच्चाई है कि भारत की घेराबंदी करने में जुटा चीन अब पाकिस्तान के बाद नेपाल को अपना मोहरा बनाना चाहता है। इसलिए वह नेपाल के विकास के नाम पर अरबों लुटाने को तैयार है। अपने सामरिक हित को ध्यान में रखते हुए उसने नेपाल में रेलवे लाईन बिछाने से लेकर बेहतरीन सड़कों के निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया है। इसके अलावा वह शिक्षा और बिजली-पानी के क्षेत्र में भी नेपाल की बढ़-चढ़कर मदद कर रहा है। नेपाल के लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से वहाँ पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला के अलावा हजारों की संख्या में स्कूल खोल रहा है। त्रासदी यह है कि नेपाल में चीन की बढ़ती दखलादांजी को वहाँ के माओवादियों का खुला समर्थन भी मिल रहा है जो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। दूसरी ओर नेपाली माओवादी भी भारत-नेपाल रिश्ते में अवरूद्ध पैदा कर रहे हैं। वे 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि का शुरूआत से ही विरोध कर रहे हैं जबकि यह संधि भारत के सामरिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। बता दें कि हि नेपाल के साथ 1950 में की गयी यह संधि इस समय भारत-नेपाल संबंधों में असहमति का एकमात्र मुद्दा है। संधि के मुताबिक नेपाल यदि हथियारों का कोई आयात करेगा तो भारत को सूचित करेगा। यह प्रावधान इसलिए है कि नेपाल को हथियारों के आयात की आवश्यकताओं की भारत से ही पूर्ति की जा सके और उसे अपनी विदेशी मुद्रा इस पर खर्च न करनी पड़े। लेकिन नेपाल द्वारा जिस तरह इस संधि को परिभाषित किया जा रहा है उससे प्रतीत होता है

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 2, Issue 5, pp: 913-917 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

कि वह इस संधि को अपनी संप्रभुता का हनन मानता है। उचित होगा कि दोनों देश इस संधि पर सकारात्मक रूख प्रदर्शित करें। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के संबंधों में कितना प्रगाढ़ता लाती है।

नेपाल इस समय मुख्य रूप से राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। हमने विगत के 60 से सामन्तवादी निरंकुशता तथा राजतंत्र के विरूद्ध और सामाजिक आर्थिक रूपान्तर के लिए संघर्ष किया। ये संघर्ष कभी शांन्तिपूर्ण रहा तो हिंसात्मक | लेकिन जिस प्रकार का संघर्ष होने पर लक्ष्य एकमात्र था सामन्तवादी निरंकुशता और राजतंत्र का अन्त और राज्य तथा समाज का प्रजातांत्रिकरण करना ही था। इसी लक्ष्य के साथ सन् 2006 में मुख्य राजनीतिक माओवादी और परम्परावादी संसदीय दलों के बीच महत्वपूर्ण सहमति हुई थी। यह सहमति संविधान सभा से राजतंत्र को अन्त कर प्रजातंत्र को संस्थागत करने के लिए किया गया था।

नेपाल राजतंत्र का अन्त करने में सफल हुए और नए प्रजातांत्रिक युग में प्रवेश किया। इस समय संविधान सभा से प्राप्त उपलब्धि को संस्थागत करने और सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण के साथ ही राज्य की संघीय पुनसंरचना करने की प्रक्रिया में है। माओवादी और तत्कालीन सरकार के बीच सन् 2006 में हुए वृहत शान्ति समझौता के अनुसार अभी हम सेना समायोजन सहित शान्ति प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण विषयों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम संविधान सभा से संविधान लिखने के काम को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही अब तक के प्राप्त उपलब्धियों को संस्थागत किया जा सकता है और हम विकास तथा परिवर्तन सहित नेपाल में प्रजातंत्र के नए युग मे प्रवेश कर सकते हैं।

इन सभी प्रक्रिया में भारत की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। नेपाल और भारत के बीच अद्वितीय संबंध है। नेपाल दो बड़े देश भारत और चीन के बीच में है। और खास कर भारत से तीन दिशाओं से हमारी सीमा जुड़ी हुई है। खुली सीमा होने की वजह से भी भौगोलिक रूप से हम तीन तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। हमारी अधिकांश आर्थिक और सामाजिक सम्बन्ध भारत से ही जुड़ा है जबकि चीन के साथ सिर्फ दस प्रतिशत होता है। भारत के साथ इस ऐतिहासिक झुकाव का कारण भी हमारा द्विपक्षीय संबंध अद्वितीय है। एक बात क्या है कि जहाँ अधिक संबंधों में निकटता होती है और अधिक सामीप्यता होती है समस्या और तनाव भी वहीं पर अधिक उत्पन्न होता है। इस समय नेपाल और भारत के बीच के संबंधों में विभिन्न विषयों पर कुछ भम्न होने के साथ सोच में भी अन्तर है। इनमें से कुछ सही भी हो सकता है तो कुछ गलत भी।

भारत ने नेपाल की शांन्ति और प्रजातंत्र की पुनर्बहाली में से लेकर संक्रमणकालीन अवस्था में सकारात्मक भूमिका अदा की है जिसकी शायद कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। नेपाल में इस समय जारी शान्ति प्रक्रिया और संविधान निर्माण के काम में भी भारत की अत्यन्त ही महत्पूर्ण भूमिका है। मेरे भारत भ्रमण के दौरान इन विषयों पर भी खुल कर चर्चा होने के अलावा इसका असर भी नेपाल पर पड़ने की संभावना है। यद्यपि नेपाल की शान्ति प्रक्रिया के सूत्रधार नेपाल के ही राजनीतिक दल हैं। तथापि इसकी सफलता के लिए भारत सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सदासयता काफी अहम मायने रखता है।

नेपाल और भारत दोनों देशों के लिए महत्पूर्ण द्विपक्षीय विषय राजनीति और सुरक्षा से संबंधित है। हिमालय की गोद में बसा हमारा सुंदर देश नेपाल एशिया के दो बड़ी महाशक्तियों की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसलिए भी भूराजनीतिक यथार्थ को भी हमें ध्यान देना होगा। हमारे पड़ोसी देशों को हमारी राजनीति और सुरक्षा संबंधी चिंता होना जायज है। इसमें नेपाल भी साझा हितों पर ध्यान दे रहा है। नेपाल के पड़ोसी देशों के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी भूमि से किसी भी पड़ोसी देश के विरूद्ध प्रयोग नहीं होने देंगे।

संदर्भ सूची:

[1]. Tyagi, Sushila, Indo – Nepalese Relations 1858-1914 (Delhi: D.K. Publishing House, 1974).
[2]. Baral, Lok Raj, "India -Nepal Relations, : Continuity and Change", Asian Survey (Berkeley), vol. 32, no. 9, September 1992 [pp. 815-829].
[3]. Ramakant, Upreti, B.C., ed., Indo-Nepal

Relations (New Delhi: South asian Publishers, 1992).
[4]. Bhattarai, Madan Kumar, Diplomatic History of Nepal (1901-1929), (New Delhi: Royal Nepalese Embassy, 1990).
[5]. Deo, A.R. "Indo-Nepal Relations", World Focus (New Delhi), Vol. 14, no. 11-12, November 1993, pp. 63-65.
[6]. G.K. Nariman Literacy History of Sanskrit , Budhism, Bombay, 1920, P. 64.
[7]. M. Winternitz, A history of indian literature, vol. II, repeirws Delhi, 1977 P-295.
[8]. L. Petech, Medival History of Nepal (750-1480) Rome, 1958, P. 101-103
[9]. S.B. Dasgupta, obscure religious cults, Culuctta, 2ded, 1963

अवासीय पता	पद / संस्था
डा0 पुष्पा कुमारी पति–जितेन्द्र कुमार मु0–सुन्दरपुर बेला, पो0–लालबाग, वार्ड नं0–04, जिला–दरभंगा पिन–846004 राज्य–बिहान मोबाईल नं0–7766938433 ई–मेल– *drpk0811@gmail.com*	**डा0 पुष्पा कुमारी** इतिहास विभाग ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा–846008 (बिहार) मोबाईल नं0–7766938433 ई–मेल– *drpk0811@gmail.com*